ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का निर्माण

906. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना आरंभ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत 13 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो आवासों के निर्माण के संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) क्या इस योजना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौंडा पाटील): (क) इस समय, देश में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 1985-86 से चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कोई अन्य योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठते।

Housing Schemes for Rural Areas

907. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what are the various housing schemes sponsored by Central Government for rural areas in the country, State-wise;

(b) the amount of Central allocations made to different States under those schemes;

(c) whether Government have a proposal to set up additional dwelling units during ninth Five Year Plan; and

(d) if so, the details regarding State-wise target set therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Indira Awaas Yojana is only scheme sponsored by the Ministry of Rural Areas and Employment for housing in rural areas in the country.

(b) State-wise Central allocation for 1998-99 under Indira Awaas yojana is given in the statement. (See below).

(c) and (d) An action Plan has been prepared by the Planning Commission for construction of about 48 lakh additional houses in rural areas during the Ninth Plan period. The Action Plan does not indicate state-wise targets.

Statement

Statewise Central Allocation during 1998-99

(Rs. in Lakhs)

Name of the State	1998-99
Andhra Pradesh	8370.41
Arunachal Pradesh	184.03
Assam	4781.82
Bihar	27420.52
Goa	19.20
Gujarat	3150.78
Hayana	1853.66
Himachal Pradesh	780.64
Jammu & Kashmir	966.16
Karnataka	6320.85
Kerala	2836.20
Madhya Pradesh	13898.74
Maharahstra	12494.77
Manipur	320.57
Meghalaya	359.16
Mizoram	83.11
Nagaland	246.36
Orissa	9574.03
Punjab	900.86
Rajasthan	4799.03
Sikkim	92.02
Tamil Nadu	7401.30